



# VISION IAS

www.visionias.in

## GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2063)

Name of Candidate	Arun Rambha		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1206249
Center	JMI, New Delhi	Date	29-10-22

### INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

### INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).  
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH**.  
इसमें बीस प्रश्न हैं हिन्दी और अंग्रेजी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**  
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.  
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.  
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.  
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.  
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2<sup>nd</sup> Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar  
Delhi- 110009

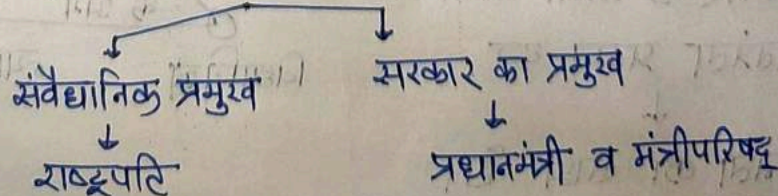
1. भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान के महत्व की व्याख्या कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)  
Explain the importance of a Constitution in the context of a democratic country like India. (Answer in 200 words) 12.5

उत्तर → संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने वाले नियमों एवं कानूनों का संहिताबद्ध समुच्चय होता है यह लिखित/अलिखित हो सकता है। लोकतांत्रिक देशों में संविधान की प्रासंगिकता अधिक बढ़ जाती है क्योंकि इस व्यवस्था में सम्पूर्ण शक्ति का स्रोत जनता ही होती है। उदाहरण- भारत का संविधान

लोकतांत्रिक देश (भारत) के संदर्भ में संविधान का महत्व

(क) शक्ति का विकेंद्रीकरण → भारतीय संविधान में शक्ति किसी एक व्यक्ति को प्रदान न करके इसे विकेंद्रित किया गया है।

जैसे:- दोहरी कार्यप्रणाली का सिद्धान्त



(ए) संघात्मक व्यवस्था का सुदृढीकरण



केन्द्र-राज्य संबन्धों (भाग-11) को विशेषतः  
निर्धारित किया गया है → सत्कारी संघवाद

(ग) कानून का शासन → देश में कानून का शासन

स्थापित हो। तथाकथित  
जंगलराज जैसी व्यवस्थाओं से परे 'विधि द्वारा  
स्थापित प्रक्रिया' एवं 'विधि की सम्यक प्रक्रिया'  
(अनुच्छेद 22) से न्याय व्यवस्था स्थापित हो।

(घ) समानता का सिद्धान्त → अनु. 14 विधि के समक्ष

समता तथा विधियों का  
समान संरक्षण पर बल देता है। भारत जैसे  
लोकतांत्रिक देशों में संविधान सामाजिक, आर्थिक  
एवं राजनीतिक समता का सुनाधार होता है।

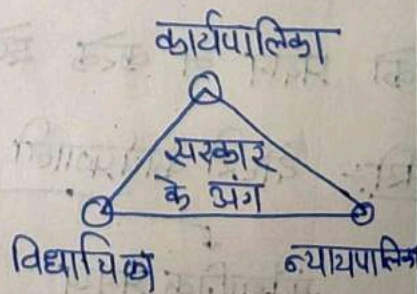
(ङ) शक्ति का पृथक्करण (SoP)

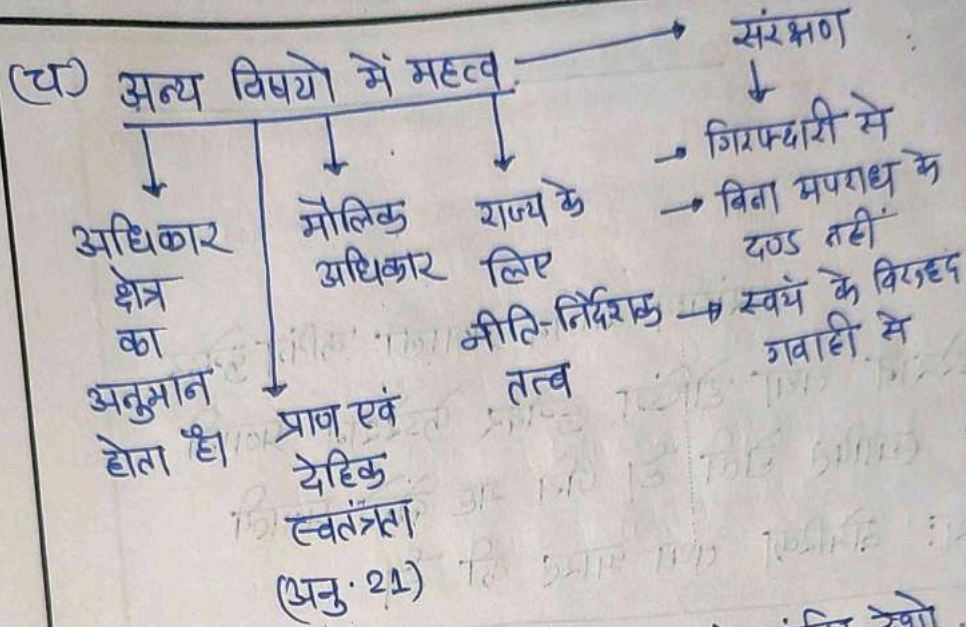


सरकार के तीनों अंगों को  
स्वतंत्रता प्रदान कर



अनला का लाभ है।





निष्कर्ष: संविधान, लोकसंगठित देशों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, गरिमायुक्त जीवन, अवसर की समानता प्रदान कर नैतिक शासन तथा लोककल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में गतिशील रहता है।

2. "साथ आकर संघ बनाने" (कमिंग टुगेदर फेडरेशन) और "सबको साथ लाकर संघ बनाने" (होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन) के बीच के अंतरों को उदाहरण सहित वर्णित कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
- Bring out the differences between 'coming together federations' and 'holding together federations' with examples. (Answer in 200 words) 12.5

संघीय शासन प्रणाली 'कमिंग टुगेदर फेडरेशन' तथा 'होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन' प्रणाली द्वारा स्थापित होती हैं। जैसे यह दोनों प्रणाली क्रमशः अमेरिका तथा भारत की हैं।

साथ आकर संघ बनाना तथा सबको साथ लाकर संघ बनाना  
(CTF) (HTF)

के प्रमुख अंतर निम्नवत् हैं -

CTF (अमेरिका)	HTF (भारत)
<p>① सभी राज्य एक साथ आकर संघ बनाने का निर्णय लेते हैं जैसे - अमेरिका के 13 दक्षिणी राज्यों ने मिलकर अमेरिका संघ की नींव रखी।</p>	<p>① संघ विभिन्न राज्यों की सहमति से तथा परिस्थिति अनुरूप अपने में समाहित कर लेता है। जैसे - भारत सभी राज्यों को साथ लाकर एक संघ बना।</p>
<p>② संघीय संरचना</p> <pre>           राज्य          /  \         /    \        /      \       /          \      /            \     /              \    /                \   /                  \  /                    \ /                      \ केन्द्र                  राज्य                     </pre> <p>दोनों शक्तिशाली</p>	<p>③ अर्द्धसंघीय व्यवस्था</p> <pre>           राज्य          /  \         /    \        /      \       /          \      /            \     /              \    /                \   /                  \  /                    \ /                      \ राज्य                    संघ                     </pre> <p>संघ शक्तिशाली</p>

CTF	HTF
<p>③ अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ</p>	<p>③ नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ (अनुच्छेद-3)</p>
<p>④ राज्यों को संघ के बराबर अधिकार</p> <p>↓</p> <p>संघीय व्यवस्थापिका में समान प्रतिनिधित्व</p> <p><u>जैसे</u> - राज्यसभा (लैनेट) में प्रत्येक राज्य से 2 लोगो का निवचन (USA)</p>	<p>④ राज्यों से राज्यसभा में सीटों का वितरण अलग-अलग भी किया जा सकता है</p> <p><u>जैसे</u> - भारत में उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटें हैं</p>
<p>⑤ राज्य के पास अधिक विधायी, प्रशासनिक, कार्यपालक तथा वित्त संबंधी शक्तियाँ</p>	<p>⑤ राज्य के पास पर्याप्त शक्तियाँ होती हैं परन्तु सूकाव केन्द्र की तरफ से संघ राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना जाता है</p>
<p>⑥ संविधान संशोधन में राज्यों की अनिवार्यतः विशिष्ट भूमिका होती है</p>	<p>⑥ साधारण बहुमत एवं विशेष बहुमत के अधिकांश संशोधन संघ द्वारा ही करती है (अनु. 368)</p>

Don't write anything in margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संघीय व्यवस्था जिसमें साथ साथ संघ बनाना की स्थिति होती है वही भारतीय संविधान ~~के~~ भारत को 'राज्यों का एक संघ' (अनु. 1) बताता है अर्थात् सबको साथ लाकर संघ बनाने का प्रावधान निहित है।

*[Faint handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page, including phrases like 'संघीय व्यवस्था', 'राज्यों का एक संघ', and 'अनु. 1']*

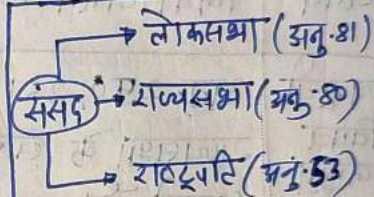
3. लोक सभा की शक्तियों की राज्य सभा की शक्तियों के साथ तुलना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Compare the powers of the Lok Sabha with that of the Rajya Sabha. (Answer in 200 words)

12.5

भारतीय संविधान अनु. 19 संसद संबंधी प्रावधानों का निम्न करता है। संसद में लोकसभा तथा राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सामान्यतः लोकसभा, राज्यसभा की तुलना में शक्तिशाली संगठन माना जाता है।

लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों की तुलना



विषय	लोकसभा	राज्यसभा
धन विधेयक (अनु. 110)	लोकसभा 73 अधिक शक्तिशाली ↓ लोकसभा अधिसूचना द्वारा निर्धारित होता है। ↓ राज्यसभा 14 दिनों में न लौटाए तो स्वतः पारित	राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में एक कंजोर संस्था है। ↓ यह इसमें संशोधन कर सकती है, परन्तु यह वाह्य-कारी प्रवृत्ति के नहीं है।
संविधान संशोधन (अनु. 368)	लोकसभा संशोधन कर सकती है। समस्त शक्ति	राज्यसभा संशोधन कर सकती है।

विषय	लोकसभा	राज्यसभा
संयुक्त बैठक (अनु. 108)	लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। ↓ लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करते हैं। ↓ संख्या बल पर विल पास करा लेते हैं।	तुलनात्मक रूप से कमजोर संस्था ↓ संख्या बल की कमी
अविश्वास प्रस्ताव	लोकसभा में ही पेश किया जाता है।	राज्यसभा पर इसका प्रभाव शून्य/नगण्य है।
राज्यसूची के विषय पर कानून	अनु. 250, 251 के तहत राज्यसभा के पास बना सकती है।	अनु. 249 के तहत विशेष शक्ति राज्यसूची पर कानून बना सकती है।
अखिल भारतीय सेवाएँ	अपर्याप्त शक्तियाँ	अनु. 312 के तहत (AIS) का निर्माण कर सकती है। हाल ही में - भारतीय कोशल विकास सेवा (ISDS) का गठन किया
भंग होना	लोकसभा भंग हो सकती है।	स्थायी संस्था, भंग नहीं होती
प्रतिनिधित्व	जनता द्वारा चुने लोगो का प्रतिनिधित्व करती है। ↓ प्रत्यक्ष चुनाव	मतान्वित तथा चुने हुए लोगो का प्रतिनिधित्व ↓ अप्रत्यक्ष का चुनाव

जहाँ राज्यसभा एवं लोकसभा को समान शक्ति है-

- (अ) बजट पर चर्चा एवं मतदान।  
 (ब) आपातकाल के समय, आपातकाल लागू करता।  
 (स) मंत्रीपरिषद् का निर्माण  $\left\{ \begin{array}{l} \text{लोकसभा दोनो से लक्ष्य} \\ \text{राज्यसभा या लक्ष्य है} \end{array} \right.$

जैसे - इन्दिरा गांधी जी एवं मनमोहन जी प्रधानमंत्री  
 राज्यसभा सफल रहे हुए केने।

(द) साधारण विधेयक को पास करना।

स्पष्टतः • संविधान अपनी प्रकृति  
 में • जनता के सदन लोकसभा को अधिक  
 शक्तियाँ प्रदान करता है परन्तु राज्यसभा भी  
 मात्र केवल एक अयोगविहीन स्टेपनी टायर नहीं है  
 उसका भी एक विशेष महत्व है।

4. न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं? साथ ही, इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)  
What do you understand by judicial activism and overreach? Also discuss the associated concerns. (Answer in 200 words) 12.5

अद्यतन लोककल्याणकारी राज्य की क्षेत्रविविधता बढ़ते हुए व्यायतंत्र भी सक्रिय होकर जनकल्याण का कार्य करते हैं। जैसे- सामाजिक याचिका (PIL) ~~का~~ द्वारा सीधे जनता के मुद्दे सुनना।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण इन्हीं व्यवस्थामों से इपेज शब्द है

**न्यायिक सक्रियता** → जब विद्यायिका शैथिल्य अवस्था में हो तथा त्वरित रूप से कार्य नहीं कर रही है तब न्यायपालिका स्वयंलक्षण लेकर विभिन्न मुद्दों का निपटारा स्वयं करने लगता है तथा नीति-निर्माण का कार्य भी करने लगता है।

जैसे :- दिल्ली सरकार को फटाखे (ब्रेकअप) बंद करने के लिए आदेश देना।

- समलैंगिकता संबंधी निर्णय प्रदान करना।

नालदा केस 2014 एवं 2018 का केस

- भवरीभाला संबंधी निर्णय इत्यादि।

व्यायुक्त अतिक्रमण → मान्डेल्स्यू का शक्ति  
पृथक्करण का सिद्धांत (SOP)

का जब हनन होने लगे अर्थात् विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य स्वयं व्यायपालिका करने लगे तब उसे व्यायुक्त अतिक्रमण कहा जाता है।

व्यायुक्त सक्रियता → व्यायुक्त अतिक्रमण से संबंधित  
प्रमुख चिंतन

(1) शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन → केन्द्र सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा लक्ष्मण शेरवा संबंधी विवादों का पिक्र मिल जाता है। व्यायुक्त अतिक्रमण से संविधान की मूल व्यवस्था व्यायुक्त तंत्र का कार्यपालिका से अलग होना (अनु. 50) का उल्लंघन है।

(2) कार्य में विश्रवाव → यदि व्यायतंत्र कार्यपालिका का कार्य करते लगे तो व्यवस्था में विश्रवाव होने की संभावना हो सकती है।

(3) जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं-

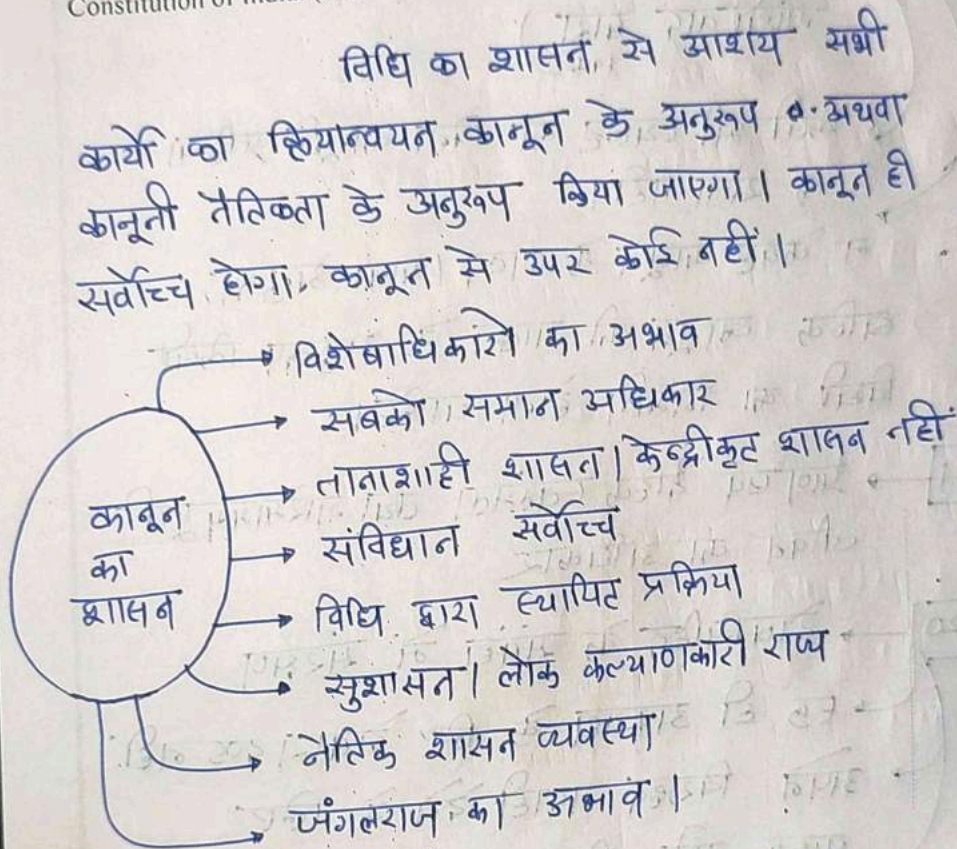
↳ इस प्रकार की व्यवस्था जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करती है जो हमारी प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' से मेल नहीं खाती।

(4) असंतुलनवाद → कार्यो में एक्सेस तथा कार्यो का इनन असंतुलनता को खगती है। मसले राष्ट्र में बड़े राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

(5) लोकतंत्र की भावना के अनुरूप तब → चुके व्यायधिश जनता द्वारा चुनकर तबे अतः उन्हे नीति निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए।

भारतीय संविधान की प्रकृति शक्ति प्रथकरण के सिद्धांत को नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत से अपनती है। अतः व्यायपालिका को व्यायिक अतिक्रमण से बचकर संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियो एवं अधिकारो के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।

5. विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि यह विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित होता है। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
- What do you understand by rule of law? Explain how this idea is reflected in the Constitution of India. (Answer in 200 words) 12.5



भारतीय संविधान में कानून का शासन

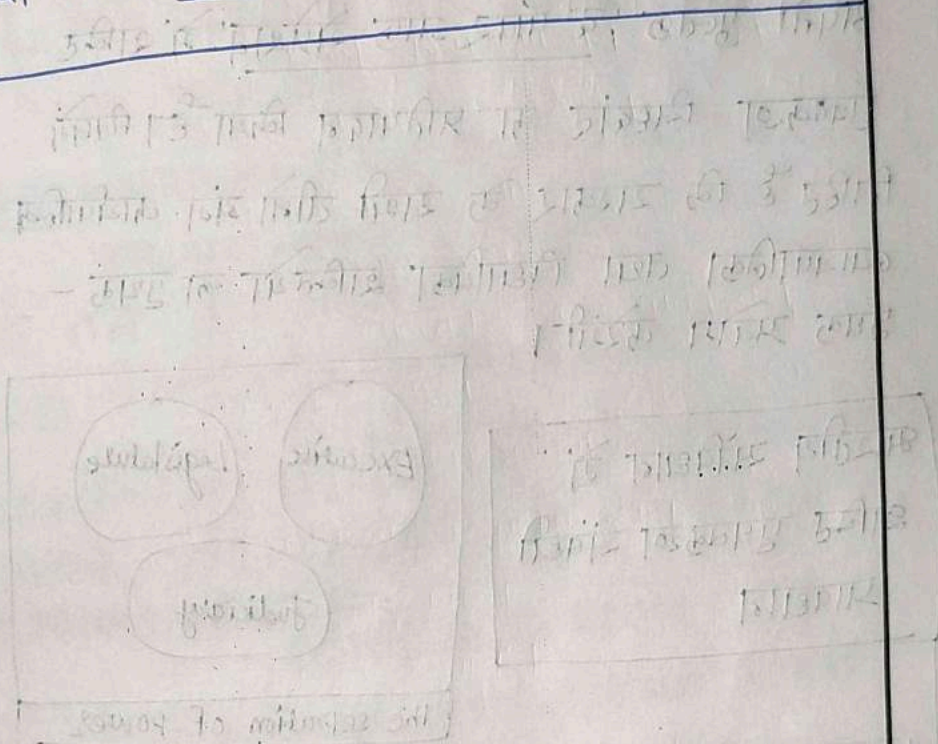
- (1) अनुच्छेद 14 → विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण

↓  
सभी नागरिकों को विधि/कानून के समान समानता प्रदान की गई है तथा कानून संबंधी उपचारत्मक प्रबंधन भी सबके लिए समान है।

- (2) अनु-21 → विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि की सम्यक प्रक्रिया (मेनका गांधीवाद द्वारा) 1978  
 किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के संजा नहीं।  
 न केवल कानून के शब्द भाषा अनुरूप, बल्कि कानून की आत्मा के अनुरूप किसी विधि का निर्माण होना चाहिए।
- (3) अनु-21 → प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तथा गरिमायुक्त पूर्ण जीवन का अधिकार
- (4) अनु-20 → दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण  
 → एक ही अपराध के लिए दोबारा दण्ड नहीं  
 → अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।  
 → झूठलक्षी दण्डित विधान से रक्षा।
- (5) अनु-22 → गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण  
 → गिरफ्तारी का कारण जानना।  
 → 24 घण्टे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (6) अनु-44 → एकसमान सिविल संहिता (UCC)
- (7) व्याधिक समीक्षा एवं पुनरावलोकन (अनु-137)

## जानून का शासन संवैधानिक वैधिका

को जीवंत बनाए रखता है तथा भारतीय नागरिकों को सशक्ति प्रदान करता है यह व्यवस्था हमें ब्रिटेन से ग्रहण की है।



संविधान के अंतर्गत कार्य - [03.12.18]

अधिकार के अंतर्गत कार्य - [15.12.18]

संघीयता के अंतर्गत कार्य - [15.12.18]

अधिकांश के अंतर्गत कार्य - [15.12.18]

संविधान के अंतर्गत कार्य - [15.12.18]

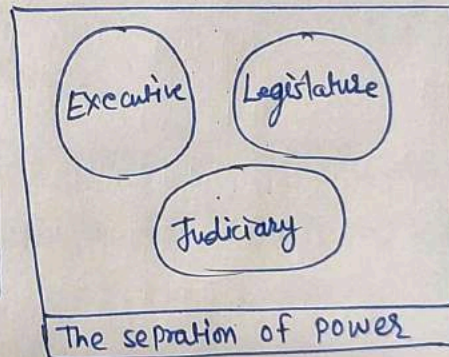
6. शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में ऐसे कौन-से प्रावधान हैं, जो शक्तियों के पृथक्करण को प्रतिबिंबित करते हैं? (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Explain the concept of separation of powers. What are the provisions in the Indian Constitution, which reflect separation of powers? (Answer in 200 words) 12.5

.... फ्रांसिसी दार्शनिक मांटेस्क्यू ने

अपनी पुस्तक 'द पावर अण्ड सेप्रेशन' में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जिसमें निहित है कि सरकार के सभी तीनों अंग कार्यपालिका (व्यायपालिका) तथा विधायिका शक्तियों का पृथक-पृथक प्रयोग करेंगी।

भारतीय संविधान में  
शक्ति पृथक्करण संबंधी  
प्रावधान



अनु-50 → कार्यपालिका का व्यायपालिका से अलग होना

↓  
राज्य के तीनों निर्देशक तत्वों में शामिल

↓  
दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र कार्य करेंगे

अनु-121 → संसद में व्यायपालिका संबंधी वाद-विवादों का वर्णन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की उन्हे पद से हटाने संबंधी प्रावधान न हो।

3) अनु. 122 → संसद की कार्यवाही/चर्चा को व्यापारिक में प्रश्न चिह्नित नहीं किया जाएगा।

4) अनु. 121 → राज्य विधानमण्डल में न्यायालय संबंधी चर्चा नहीं।

5) अनु. 212 → उच्च न्यायालय में राज्य विधानमण्डल संबंधी चर्चा नहीं।

6) अनु. 361 → कार्यपालक प्रमुख राष्ट्रपति तथा राज्यपाल जब पद स्थापित हैं तब उन्हें न्यायालय दण्ड नहीं सूना सकता।

7) अनु. 105 → सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार  
↓  
जब संसद का सत्र चल रहा हो तब उन्हें व्यापारिक अपने समक्ष जबरजस्ती नहीं बुला सकती।

8) 99 वा संविधान संशोधन रद्द।  
: दयालु है कि भारतीय राजव्यवस्था

अमेरिका की तरह निरपेक्षतः शक्ति पृथक्करण को नहीं स्वीकारती वरन् नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करती है।

शक्ति संतुलन संबंधी प्रावधान

- कार्यपालिका, विधायिका का ही संग
- कार्यपालिका की मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामुहिक उत्तरदायी (अनु. 75)
- न्यायाधिश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
- उच्च न्यायालय के न्यायाधिशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल की सहमति
- न्यायिक सक्रियता

Don't write anything this margin  
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्टतः शक्ति प्रयत्न का भारतीय मॉडल शक्ति 'चेक एण्ड बेलेय' सिद्धांत को अपनाता है यह तीन अंगों की कार्यकुशलता की दक्षता एवं प्रभावशीलता बलून हेतु आवश्यक है।

*[Faint handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page, including phrases like 'अपनाता है', 'दक्षता एवं प्रभावशीलता', and 'बलून हेतु आवश्यक है']*

7. भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)  
 Discuss the veto powers of the President of India. (Answer in 200 words) 12.5

भारतीय संविधान अनु 111

राष्ट्रपति द्वारा विधेयको पर सहमति संबंधी प्रावधान करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को कुछ वीटो शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं।

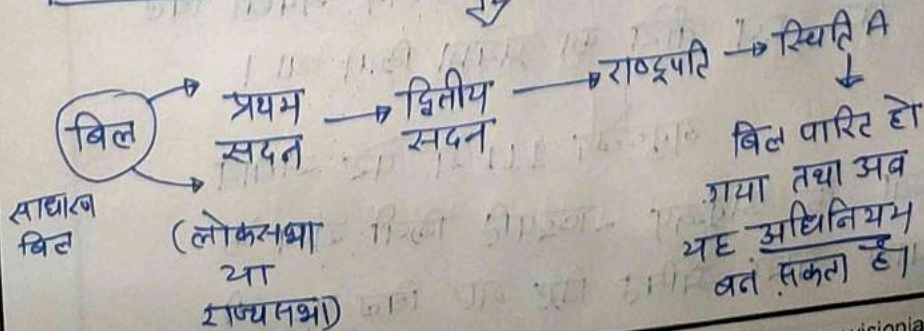
### राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

- ① परमानिषेधा अधिकार
- ② आत्यंतिक शक्ति (Absolute power)
- ③ जेबी अधिकार (pocket veto)

वीटो पावर  
 विशेष प्रकार की शक्ति → हाँ या ना में होती है

④ परमानिषेधाधिकार → राष्ट्रपति किसी विधेयक पर  
 (A) सहमति दे सकता है।  
 (B) सहमति शक देते है।

स्थिति-A → सहमति दे देते है अर्थात्



स्थिति-B → सभ्यति शेकु देते हैं → मिनी बिल पर  
राष्ट्रपति अपनी सभ्यति को शेकु देते  
हैं तथा शेकुने के कारण को स्पष्ट कर देते हैं।

↓  
बिल पुनः सदन में चला जाता है।

② आत्यांतिक वीटो शक्ति → मिनी विधेयक बिल  
पर अपनी सभ्यति  
शेकु देते हैं तथा कारण स्पष्ट नहीं करते हैं।

↓  
बिल, इस स्थिति में भी अधिनियम नहीं बनता।

③ जेवी निषेधाधिकार → यह सबसे रोमांचक वीटो शक्ति  
का एक प्रकार है जिसमें

राष्ट्रपति मिनी विधेयक को अपने पास रख  
लेता है उस पर मिनी प्रकार की प्रतिक्रिया  
नहीं देते।

उदाहरण :- राजीव गांधी सरकार के समय राष्ट्रपति  
ज्ञानी जैब सिंह ने डाकपत्र संबंधी बिल

पर इस वीटो का प्रयोग किया था।

↓  
अनुच्छेद 111 में पर संघीय

प्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति मिनी राज्य के  
राज्यपाल द्वारा प्रेषित किए गए बिल पर भी

अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है।

द्वारा तय है कि संविधान मूल संविधान में बिल को सदन द्वारा पुनः राष्ट्रपति को प्रेषित करने बाबत विशेष प्रावधान नहीं था परन्तु संविधान संशोधन द्वारा दोबारा ब्रेजे गए बिल पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है।

स्थिति: राष्ट्रपति जो की संवैधानिक कार्यालय प्रमुख होता है साथ ही संसद का एक अंग भी होता है, को विधेयको पर चर्चा की संस्कृति बढाने - पुनर्विचार करते तथा संशोधित करने हेतु राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई है।

विधेयको को राष्ट्रपति को प्रेषित करने के लिए संसद द्वारा पारित किया जाता है।

यदि राष्ट्रपति विधेयको को वापस भेजता है तो संसद इसे पुनः पारित कर सकती है।

यदि राष्ट्रपति विधेयको को वापस भेजता है तो संसद इसे पुनः पारित कर सकती है।

यदि राष्ट्रपति विधेयको को वापस भेजता है तो संसद इसे पुनः पारित कर सकती है।

यदि राष्ट्रपति विधेयको को वापस भेजता है तो संसद इसे पुनः पारित कर सकती है।

यदि राष्ट्रपति विधेयको को वापस भेजता है तो संसद इसे पुनः पारित कर सकती है।

यदि राष्ट्रपति विधेयको को वापस भेजता है तो संसद इसे पुनः पारित कर सकती है।

8. भारत में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में विभागीय स्थायी समितियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Discuss the role of the Departmentally Related Standing Committees in strengthening parliamentary democracy in India. (Answer in 200 words) 12.5

संसद में अत्यधिक कार्य की  
अद्विष्टता, समय अभाव तथा सांसदों का लेयमेन नेचर  
विभागीय स्थायी समितियों के सृजन से बनवती  
बनाता है। ये समितियाँ संसदीय लोकतंत्र को  
सुदृढ़ता प्रदान करती हैं।

स्थायी समितियाँ — जिनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है  
तथा स्थायी प्रकृति की होती हैं।

जैसे — लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति (EC)  
सार्वजनिक उपक्रम समिति (PUCs) इत्यादि।

संसदीय लोकतंत्र की मजबूती में इन समितियों की भूमिका

(क) विपक्ष की भूमिका → कई संसदीय समितियों में विपक्ष के  
बेता अध्यक्ष होते हैं।

साथ ही इन्हें अन्य विचारधाराओं से संबंधित  
संवादगण होते हैं। • इन्हें यह समितियाँ  
विपक्ष की भूमिका का निर्वहण करती हैं।

↓  
लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण + चर्चा की संस्कृति में वृद्धि

(ख) सार्वजनिक धन पर नियंत्रण → लोक लेखा समिति (LS+T)

तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक वित्त तथा खोपे गए वित्तीय विषयों की लेखा परीक्षा (अक्रडेंटींग) करती है। इसमें (AP) इनकी सहायता भी करता है।

↓  
जनता के धन का सुदुर्योग करने पर बल।

(ग) विभिन्न विचारधाराओं का समूह → समितियों में अधिकांशतः विभिन्न

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं जो किसी विषय पर अपनी पार्टी के विचारों को पेश करते हैं → लोकतंत्र में वृद्धि।

(घ) नीति निर्माण में पारदर्शिता → स्थायी समितियों के समक्ष विभिन्न बिलों

को भेजने से नीति-निर्माण में उदारता, पारदर्शिता तथा सहिष्णु विचारों का समावेश होता है जो जनतांत्रिक संसद की अवधारणा को बढ़ाता है।

(ङ) सत्ताशुद्ध दल की प्रचण्ड संख्या बल पर लगाम

↓  
प्रचण्ड बहुमत वाली सरकार अपने बिलों को 'गिलोटीन' प्रक्रिया से पास करा लेती है—

परन्तु यह 'ताताशाही लोकतंत्र' को बढ़ाता है।

↓  
बिल को स्थायी समितियों में भेजने से विस्तारपूर्वक  
गंभीर चर्चा हो जाती है।

निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि

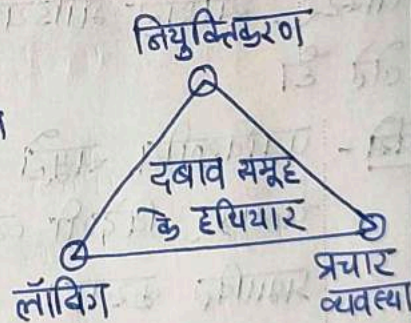
विभागीय स्थायी समितियाँ जनता की आवांसाओं  
के अनुरूप विभिन्न प्रायों का बहुआयामी  
अध्ययन कर तथा सभी दलों के विचारों  
को सुनकर लोकतंत्र को उत्तमयित करता है।

9. दबाव समूहों से आप क्या समझते हैं? दबाव समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
- What do you understand by pressure groups? Citing examples, state the different types of techniques used by pressure groups. (Answer in 200 words) 12.5

दबाव समूह समान विचारधाराओं तथा हितों वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो अपने मांगों की पूर्ति कियाने हेतु नीतियों को अपने अनुसार अनुकूल बनवाने की मांग करते हैं। जैसे - FICCI, एसोचैम, NSUI, विहिप आदि।

दबाव समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन

- (1) औडिगार्ड के अनुसार, दबाव समूह मुख्यतः तीन तरीकों से नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं -



(क) नियुक्तिकरण

→ विभिन्न शासकीय एवं प्रशासकीय पदों पर अपने हित समकक्ष व्यक्ति की नियुक्ति पर बल देते हैं।

जैसे - किसान समूह के आंदोलन में केंद्रीय मंत्री 'हरसिमरत कौर' का इस्तीफा देना।

1. (ख) लॉबिंग → दबाव समूह गठजोड़ तथा साठगाठ का प्रयास कर नीतियों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं।

जैसे - अनौपचारिक संगठनों द्वारा प्रशासनिक गठजोड़ का प्रयास।

(ग) प्रचार व्यवस्था → अधिक जनधार बढ़ाने के लिए तथा अपनी बातों को

जल्दा तक पहुँचाने के लिए प्रेस, मीडिया, पोस्टर, सोशल मीडिया इत्यादि का सहारा लेते हैं।

जैसे - पर्यावरणीय समूहों द्वारा 'ट्विटर आंदोलन' चलाकर विदेशी व्यक्तियों तक को प्रभावित करना।

(2) हिंसात्मक साधन

→ दबाव समूह कभी-कभी हिंसात्मक साधनों जैसे - हड़ताल, सार्वजनिक वस्तुओं की तोड़-फोड़, सड़क बंद, शेकना जलाना इत्यादि करते हैं।

जैसे - अग्निवीर योजना के समय अनौपचारिक

दबाव समूहों द्वारा ट्रेन/बस इत्यादि जलाना।

(3) बजट निर्माण प्रक्रिया में → बजट निर्माण से पूर्व  
वित्त मंत्रालय विभिन्न

हितधारकों से चर्चा तथा प्रतिसंकरण (फीडबैक)

लेता है।

जैसे: फिक्की, किसान समूहों इत्यादि से बात करना।

(4) चुनाव इंजीनियरिंग → चुनाव पूर्व विभिन्न तरीकों  
से दबाव समूह अपनी मांगों

के अनुरूप मनिफेस्टो (घोषणा पत्र) जारी करने  
की बात करते हैं।

जैसे: आरक्षण संबंधी मांग इत्यादि।

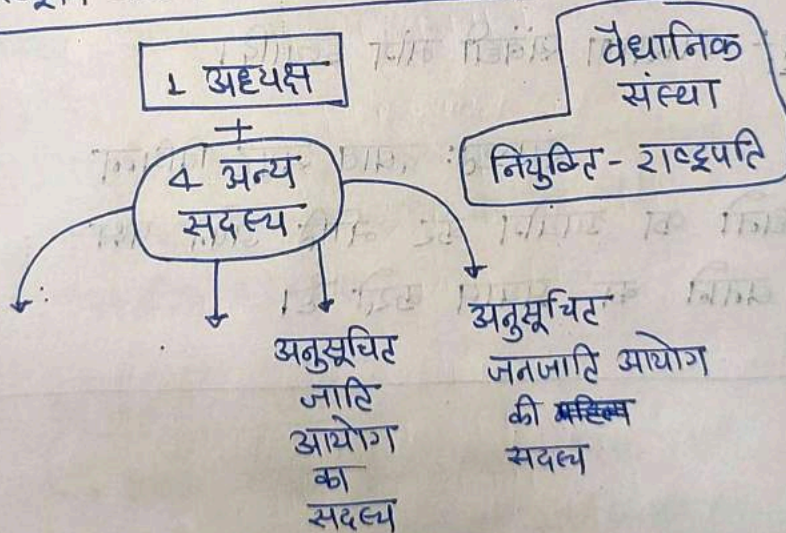
स्पष्ट: दबाव समूह विभिन्न  
साधनों का उपयोग कर नीति अपने पक्ष  
में बनाने का प्रयास करते हैं।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की संरचना और कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए इस आयोग द्वारा प्रारंभ पहलों को रेखांकित कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Enumerate the composition and functions of the National Commission for Women (NCW). Also, highlight the initiatives taken by the Commission to give an impetus to women empowerment. (Answer in 200 words) 12.5

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1993 में महिलाओं के सशक्तीकरण, जीवन स्तर में सुधार तथा उनके विरुद्ध हो रही हिंसा एवं शोषण को समाप्त करने के लिए की गई थी।

### राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना



### राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य

- (1) महिलाओं का सर्वांगीण विकास, सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करना।

- (2) महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा/शोषण का संज्ञान लेना → दोषी को सजा सुनाना।  
जैसे - हालिया समय में ▷ राजस्थान की एक महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार थी। महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला स्पष्ट किया।
- (3) महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न पेट्रोल, जैसे महिला साथी, सहेली इत्यादि की शुरुआत कर उनकी रक्षा करना।
- (4) कार्यस्थल पर हो रही यौन हिंसा के विरुद्ध कार्य करना। जैसे भारतीय में #Meetoo आंदोलन पर महिला आयोग की चैनी नज़र हो
- (5) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करना।
- (6) हर वर्ग की महिला पितृत्व, किशोरी, युवा, प्रेक्षक एवं वृद्धों भी शामिल हैं, के गरिमायुक्त जीवन का ध्यान रखना।
- (7) विभिन्न मंत्रालयों, प्रशासनिक कार्यालयों तथा राज्य विभागों से संपर्क बनाकर महिलाओं के हितों की रक्षा करना। आदि।

महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए  
आयोग द्वारा की गई पहले -

(क) पेट्रोलर्स की शुरुआत → मेरी सहेली, महिला  
मित्र इत्यादि की शुरुआत।

(ख) आपातकालीन नंबर → 24x7 उपस्थित  
→ 1098 बच्चियों के लिए  
→ 112 महिलाओं के लिए  
→ 'Dial 100' केम्पेन

(ग) सुरक्षा संबंधी कौशल → करंट ट्रेनिंग तथा कई  
सेवाएँ → सुरक्षा को बढ़ावा।

(घ) कानूनी लड़ाई → क्रिमिनल एक्ट 2013 में संशोधन

↓  
2018 > महिला सुरक्षा  
→ त्रिपल तलाक़ संबंधी बिल 2018

(ङ) वन स्टॉप सेंटर, महिला बजट को प्रोत्साहन,  
महिलोन्मुखी योजनाओं जैसे संबल योजना,  
मिश्र शक्ति इत्यादि को बढ़ावा देना।

स्पष्टतः राष्ट्रीय महिला आयोग  
महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने  
के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध वैधानिक संस्थान है।

11. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों के हस्तांतरण पर प्रकाश डालिए। क्या आपको लगता है कि हस्तांतरण की प्रक्रिया अब तक संतोषजनक स्तर से कम रही है? (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Highlight the devolution of powers under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. Do you think the process of devolution has been less than satisfactory so far? (Answer in 200 words) 12.5

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा स्वशासन की स्थापना हेतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 को लाया गया। ये संशोधन 'तृणमूल सरकार' बनाने को प्रतिबद्ध है।

केन्द्रीय शक्ति का हस्तांतरण → विकेंद्रीकरण की वास्तविकता

विलेज डेमोक्रेसी के लेखक शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को 'प्रसंतोषजनक मानकर इसे 'गुड थ्योरि बट बेड प्रैक्टिस' कहते हैं क्योंकि -

(1) अवांछनीय हस्तक्षेप

→ नौकरशाही तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों (MP, MLA) इत्यादि का पंचायतों पर अवांछनीय प्रभाव एवं हस्तक्षेप रहता है।

↓  
शक्ति का सम्पूर्ण उपयोग पंचायत प्रतिनिधि कर नहीं पाते → (शक्ति का विभेदीकरण)

(2) वित्तीय अपंगता → राज्य वित्त आयोग की स्थापना के बावजूद करों (TAX) का एकीकरण संसुष्टिजनक रूप से नहीं होता। साथ ही राज्य विधानमंडल भी अपर्याप्त अनुदान प्रदान करते हैं। अनुदान का बड़ा अंश 'बिचौलिया संस्कृति' से ब्रह्मचार की भेंट चढ़ जाता है।

(3) प्रकार्यात्मक कमी → स्थानीय स्वशासन में कार्यरत 'कुंकशनरीज' अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से नहीं करते। नीतियाँ अच्छी बनी हुई हैं परन्तु क्रियान्वयन संबंधी समस्याएँ हैं।

(4) समानान्तर संस्थाएँ → नगरीय निकायों में कई समानान्तर संस्थाएँ कार्य करती हैं जिससे कार्यों का दोहराव एवं शक्ति का दुरुपयोग भी होता है।  
जैसे - दिल्ली जल बोर्ड, इत्यादि।

(5) पुरुषवादी सोच → सरपंच पति, अध्यक्ष पति

+  
आरक्षण की 'यक्रीय पहचति'

↳ समावेशी सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान नहीं करती।

परन्तु यदि निष्पक्ष प्रत्येयता की जाए तो हम पाएंगे की स्थानीय स्वशासन ने लोकतंत्र को एक विधिक शब्दावली की जगह लोगों की जीवनशैली का एक प्रथिन गंज बना दिया है। इसके साथ ही -

- (1) महिला आरक्षण →  $\frac{1}{3}$  महिलाओं / ST-SC को अनिवार्य आरक्षण।  
(अनु. 243 D & T)

पूरे भारत में >1.50 लाख महिलाएँ सीधे जनता द्वारा चुनी जाती हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में यह बड़ा कदम है।

- (2) स्वशासन की स्थापना।  
(3) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण का मूर्त रूप।  
(4) बढ़ती जनभागीदारी तथा लोकतंत्र की लोकप्रियता इत्यादि।

तटस्थ होकर यदि स्थानीय स्वशासन के पिछले 3 दशकों का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि कुछ चुनौतियों के प्रतिरिक्त यह सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा सफल होने की ओर अग्रसर है।

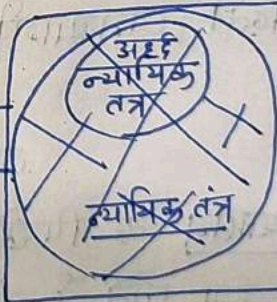
12. यद्यपि अर्ध-न्यायिक निकायों को न्यायिक निकायों के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं तथापि दोनों के बीच अंतर के अनेक महत्वपूर्ण बिंदु विद्यमान हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Although quasi-judicial bodies have powers resembling those of the judicial bodies, there are important points of distinction between the two. Elaborate. (Answer in 200 words) 12.5

अर्ध-न्यायिक निकाय से आशय ऐसे निकाय पिनडे कुछ मामले (सामान्यतः सिविल) में न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। अर्थात् इन्हे दण्ड देने। शास्ति लगाने का अधिकार प्राप्त होता है।  
जैसे - प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) इत्यादि।

अर्ध-न्यायिक निकाय को न्यायिक तंत्रों के समान शक्ति प्राप्त होती है परन्तु न्यायिक तंत्रों से भिन्न होते हैं-

अर्ध-न्यायिक निकाय	न्यायिक तंत्र
(1) इनका नियमन किसी विशेष कार्य के लिए होता है परन्तु यह अपराधियों को सजा का प्रावधान भी कर सकते हैं। जैसे - CAT	(1) इनका नियमन विशेषतः न्याय प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। यह सिविल एवं फौजदारी दोनों मामलों में सजा सुना सकते हैं। जैसे - SC, High Court.



अहर्द-न्यायिक निकाय	न्यायिक निकाय
(2) सामान्यतः सिविल मामले को ही सुनते हैं।	(2) सिविल, दण्डितया संवैधानिक मामले को सुनते हैं।
(3) इनके विरुद्ध अपील HC, SC में की जा सकती है।	(3) SC अंतिम अपीलिय न्यायालय होता है।
(4) कठोर दण्ड तथा मृत्युदण्ड का प्रावधान नहीं कर सकते हैं।	(4) मृत्युदण्ड/जंजी आदि का भी प्रावधान कर सकते हैं।
(5) अहर्द-न्यायिक निकाय ↓ दण्ड + प्रशासनिक मुद्दा	(5) न्यायिक निकाय ↓ दण्ड + कानूनी मुद्दा
(6) मुख्यतः प्रशासकीय एवं प्रबंधन संबंधी कार्य को देखते हैं। <u>जैसे</u> - Art. 323 (B) में वर्षि अधिकरण	(6) मुख्यतः कानूनी एवं न्यायिक विषयों को देखते हैं।
(7) मुख्य कार्य → जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उसे पूरा करने का प्रयास करना।	(7) मुख्य कार्य ↓ कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना तथा सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करना

Don't write anything this margin  
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्टतः अर्द्ध न्यायिक

निकाय प्रशासन, प्रबंधन तथा दंड से जुड़े हैं वही न्यायिक निकाय मुख्यतः

दाखिल व्यवस्था से जुड़े हुए हैं

निकाय प्रशासन (1)

निकाय प्रशासन विभाग  
इस विभाग में

प्रशासनिक सुविधाएं (2)

निकाय प्रशासन + 20%

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं (3)

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं  
इस विभाग में

निकाय प्रशासन (4)

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं  
निकाय प्रशासनिक सुविधाएं  
निकाय प्रशासनिक सुविधाएं  
निकाय प्रशासनिक सुविधाएं  
निकाय प्रशासनिक सुविधाएं

निकाय प्रशासन (1)

निकाय प्रशासन विभाग  
इस विभाग में

प्रशासनिक सुविधाएं (2)

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं + 20%

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं (3)

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं  
इस विभाग में

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं (4)

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं (5)

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं (6)

निकाय प्रशासनिक सुविधाएं (7)

13. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत निरहता के श्रावणों को वर्गीकृत कीजिए। साथ ही, निरह प्रतिनिधियों के लिए उपाययुक्त उपायों पर भी चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Delincate the grounds of disqualification under the Representation of the People Act, 1951. Also, discuss the remedial measures available to the disqualified representatives. (Answer in 200 words)

12.5

**लोकप्रतिनिधि अधिनियम (RopA) 1951**

संलग्न पत्राचार के प्रावधानों को निश्चित करने हेतु तथा जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में विशिष्ट प्रावधान करना है।

**RopA, 1951 के तहत निरहता के आधार**

- (क) क्षुद्राचार में संलग्नता।
- (ख) चुनाव के समय धांधली प्रयुक्त आवश्यकता से अधिक रकम जुतने पर।
- (ग) किसी प्रचाराय में 2 साल से अधिक सजा कटने पर।
- (घ) 60 दिन से अधिक लगातार संसदीय सदन में उपस्थित नहीं होने पर।
- (ङ) श्रावण आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन पर।
- (च) चुनाव के समय राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीको तथा संविधान के संदर्भ में घृणित लिपि करने पर इत्यादि।

RoPA 1951 निरट्टे व्यबिन्दु

के रक्षोणाय (उपचारत्मक) साधन की प्रदान करता है। ये साधन है -

- (क) बरदरपति के सम्मक्ष याचना।
- (ख) निर्वाचन आयोग संबंधी विधाननिर्देश।
- (ग) न्यायालय के सम्मक्ष मुद्दे को ले जाना इत्यादि

। उ। प्रश्न समाधान 2063

शासन के निर्वाचन मुद्दे के (2061, 1992)

। प्रश्नकोश में शामिल है।

समाधान: प्रश्न निर्वाचन मुद्दे के निर्वाचन (2)

। उ। निर्वाचन मुद्दे सम्बंधित है।

उत्तर: प्रश्न के अनुसार निर्वाचन मुद्दे

। उ। निर्वाचन मुद्दे

प्रश्न निर्वाचन मुद्दे सम्बंधित है। प्रश्न (2)

। उ। निर्वाचन मुद्दे सम्बंधित है।

। उ। निर्वाचन मुद्दे (2061) निर्वाचन मुद्दे सम्बंधित है।

निर्वाचन मुद्दे सम्बंधित है। प्रश्न (2)

निर्वाचन मुद्दे सम्बंधित है। प्रश्न (2)

निर्वाचन मुद्दे सम्बंधित है।

14. भारतीय संविधान की मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) का सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार है।  
विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)  
The basic structure doctrine of the Indian Constitution is a judicial innovation.  
Analyse. (Answer in 200 words) 12.5

केशवामन्द भारती बनाम भारत  
संघ (1973) के मामले में न्यायपालिका ने  
ऐतिहासिक न्यायिक नवाचार संबंधी मूल ढांचे  
(Basic structure) का सिद्धांत दिया। यह  
संवैधानिक नैतिकता को जीवन्तता प्रदान करता है।

मूल ढांचा/संरचना से आशय  
संविधान के प्रमुख मूल्य जिनमें संविधान  
की आत्मा बसती है, को बनाए रखने पर  
बल दिया है।  
जैसे - लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, अनु. 32 इत्यादि।

मूल संरचना का सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार

अब तक की संविधान की सबसे बड़ी बेंच-13  
जनों की बेंच-द्वारा दिया गया फैसला

अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 संबंधी विभिन्न  
विवादों का समापन कर दिया

↓  
विधायिका संविधान के किसी भी भाग को संशोधित

कर सकती है, वशते मूल ढांचा बना रहे।

- भारतीय संविधानिक तंत्र के अतिरिक्त अन्य संविधानों में मूल संरचना संबंधी प्रावधान विश्ले ही मिलते हैं।
- मूल संरचना का निश्चिण समय-समय पर न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा > नवाचार
- 1973 से पहले गौलकनाथ केस, बेरुबाड़ी केस, A.K. गौपालन केस इत्यादि में यह दिशाई नहीं देता है। → केशवानंद भारती केस में दिशा।
- भारतीय न्यायपीठ द्वारा दिए गए प्रमुख निणयो में सबसे प्रेष्ठ तथा सर्वोच्च मौलिक निणय।
- न्यायिक समीक्षा तथा न्यायिक पुनरावलोकन और अनुसूची-9 में संबंधित समस्त प्रसलो का निराकरण कर दिया।
- कार्यपालिका अपने प्रचण्ड बहुमत के बल पर पुनः 1976 (42 वाँ संविधान संशोधन) जैसे संशोधन न करे → इस हेतु यह निणय ग्रहण है।
- संवैधानिक मूल्यों का समायोजन।
- शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत अनुसार।

निःसंदेह मूल संस्कृति संबंधी मामले को न्यायिक तवाचार की संज्ञा दी जा सकती है जो 'कोन्स्टिट्यूशनल मोरल्टी' की भावना के अनुरूप है।

*[Faint handwritten notes in Hindi, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page.]*

15. भारत में सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करने में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। साथ ही, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Highlight the various challenges in ensuring cooperative federalism in India. Also, suggest measures to foster cooperative federalism. (Answer in 200 words) 12.5

सहकारी संघवाद से आशय  
केन्द्र एवं राज्य विभिन्न नीतियों एवं क्रियाओं  
का निर्माण। कार्यन्वयन आपसी सांभंजस्य  
तथा सहयोग से करे। यह केन्द्र-राज्य तथा  
राज्य-राज्य में समरसता बढ़ाता है।

संघवाद की वास्तविक धरातल पर  
हमें इतने कई चुनौतियाँ भी दिखती हैं जो  
झगडालू संघवाद की बढ़ावा देती हैं। ये प्रमुख  
चुनौतियाँ -

(1) विधायी चुनौतियाँ

→ (क) राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा  
कानून बनाना। [अनु. 249, 250, 251]

→ (ख) अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास [अनु. 248]

→ (ग) समवर्ती सूची पर कानून बनाने की  
अधिक शक्ति संघ के पास [अनु. 246]

(घ) विषयो का  
असमान  
वितरण

← संघ सूची  
← समवर्ती सूची  
← राज्य सूची

↑ नीचे से ऊपर  
जाने पर विषय  
बढ़ते हैं

(8) किसी राज्य विधानमण्डल के बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजना।

### (2) प्रशासकीय संबंध चुनौतियाँ

- राष्ट्रपति शासन (अनु. 356)
- किसी भू-भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल (352)
- राज्यपाल की नियुक्ति (अनु. 153)
- अखिल भारतीय सेवाओं की राज्यों में नियुक्ति।
- अर्द्ध केन्द्रीय बलों (CAPF), कैंग (CAJ), CBI, ED इत्यादि दलों को जांच के लिए भेजना।

### (3) वित्तीय चुनौतियाँ

- कर संग्रहण अधिक → केन्द्र के पास।
- करों का उचित तथा समयानुरूप बँटवारा नहीं।
- वित्तीय आपातकाल > धन विधेयकों को रोकना।
- केन्द्र द्वारा राजनीतिक समरूपता वाले राज्यों को अधिक ऋण एवं अनुदान देना।
- प्रमुख करों को अपने पास रखना।
- GST परिषद् में केन्द्र के वोट का भारांश  $\frac{1}{3}$  तथा समस्त राज्यों का भारांश  $\frac{2}{3}$  होना।
- विदेशी संस्थाओं से ऋण लेने की शक्ति केवल संघ सरकार के पास।

इस प्रकार की स्थितियाँ चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं अतः सहकारी संघवाद

को बढ़ाने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए -

- (1) **विधायी प्रयास** → अवशिष्ट विषय, समवर्ती सूची विषय तथा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने से पूर्व राज्यों से पूछना चाहिए।
- (2) **प्रशासकीय उपाय** → राज्यपाल > भगवान सहाय समिति की सिफारिशें मानना चाहिए।  
 → सरिकल भारतीय सेवास → अनु. 310/311 का सरलीकरण  
 → राष्ट्रपति शासन > केवल अपवाद स्वरूप स्थिति में ही।

- (3) राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देना।
- (4) वैधानिक उपकरण → क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, (262) नदी जल निपटान प्राधिकरण (263) इत्यादि।
- (5) नैसर्गिक उपकरण → नीति आयोग, राष्ट्रीय एका परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि।
- (6) भौपचारिक उपकरण → मन्त्रिमंत्रियों, मन्त्रियों के सम्मेलन, प्रशासनिक अधिकारियों तथा सचिवों का सम्मेलन इत्यादि।

अप्युक्त विन्दुओं पर ध्यानपूर्वक करके सहकारी संघवाद को स्वस्थ एवं प्रतियक्षी बनाया जा सकता है।

16. कई सारे देशों के संविधानों से उधार ली गई विशेषताओं के बावजूद, भारत का संविधान अद्वितीय बना हुआ है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Despite having features borrowed from Constitutions of various other countries, the Constitution of India remains unique. Discuss. (Answer in 200 words) 12.5

डॉ. बी. आर अम्बेडकर ने

संविधान के संदर्भ में कहा था कि "इसमें कई देशों के संविधानों के नैतिक तत्वों को भारतीय स्थिति अनुरूप स्वीकार कर लिया गया है।"

आलोचक भारतीय संविधान को 'उधार का खेल' भी कहते हैं परन्तु फिर भी भारतीय संविधान अपनी प्रकृति में अद्वितीय है।

**भारतीय संविधान के स्रोत**

- क) अमेरिका → न्यायालय की सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, न्यायिक लक्ष्मण
- ख) ब्रिटेन → एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि द्वारा स्थापित प्रशासन, कानून का शासन,
- ग) जर्मनी → आपातकालीन प्रावधान।
- घ) फ्रांस → समानता, स्वतंत्रता, बंधुता।
- ङ) रूस → मौलिक कर्तव्य।
- च) आयरलैंड → DPSP, राज्यसभा में मनोनयन
- छ) दक्षिण अफ्रीका → संविधान संशोधन।

इसके अतिरिक्त 1935 ई. के भारत शासन अधि. से भी हमने कई तत्वों को स्वीकारा है।  
इसके बावजूद हमारे संविधान की अद्वितीयता।

(1) कठोर और नम्य → संविधान संशोधन न अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर है और न ही ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता

↓  
जैसे - नागरिकता संबंधी विषय पर साधारण बिल मूल अधिकार के लिए कठोर प्रक्रिया।

(2) संघात्मक व्यवस्था → भारतीय संघवाद राज्यों का एक संघ के रूप में केंद्र की तरफ झुका हुआ है।

(3) गणतंत्रात्मक → ब्रिटेन की तरह राजशाही नहीं है अपितु अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद दिया गया है।

(4) स्थानीय स्वशासन → भारतीय संविधान अनु. 40 तथा 13/14 के संविधान संशोधन पृथक् सरकार का प्रावधान करते हैं।

(5) न्यायपालिका का कालेजियम प्रणाली  
↳ भारतीय संविधान की यह मौलिक व्यवस्था है जो अन्यत्र विश्व में पुरस्कृत है।

(6) नागरिकों को प्रदान किए मौलिक अधिकार

- ↳ 6 प्रमुख मौलिक अधिकार
- ↳ निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार इत्यादि प्रदान किया।

(7) संसदीय शासन प्रणाली में जीरो हॉवर (Zero Hour) भारतीयों की उपज है।

(8) संसदीय संप्रभुता की जगह संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया तथा शक्ति का केन्द्र जनता को रखा।

(9) पंथनिरपेक्षता {

- ↳ सकारात्मक मॉडल अपनाया।
- ↳ राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा वह सभी धर्मों का सम्मान करेगा।

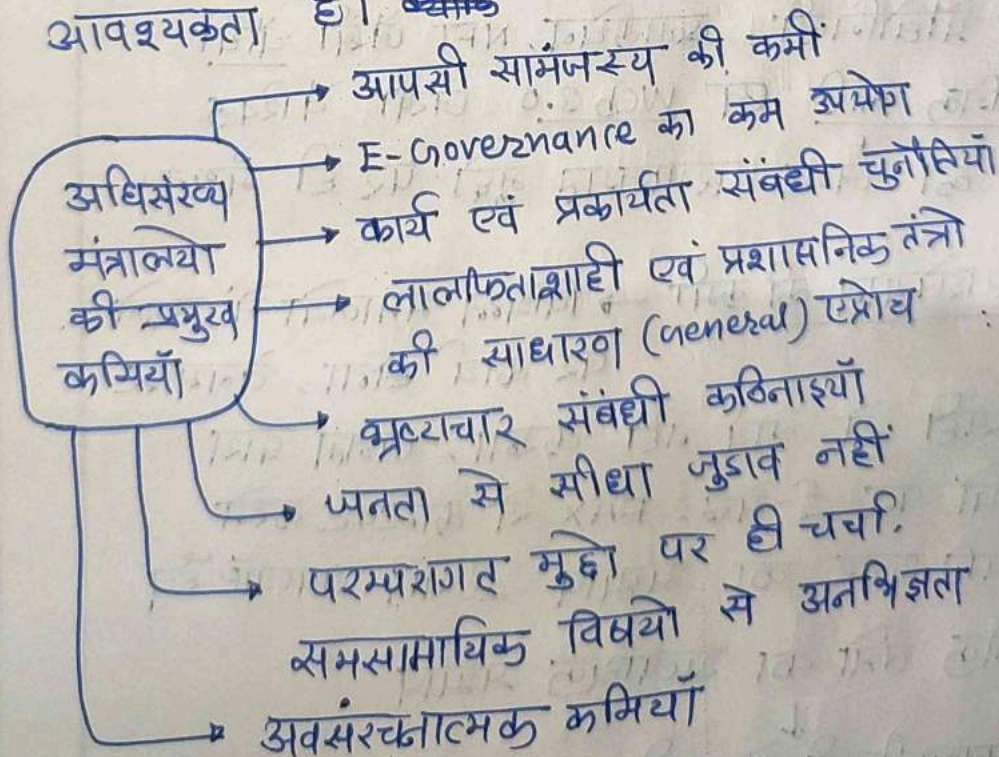
 (अनु. 25 से 28) इत्यादि।

~~विशेष~~ अस्तु कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा एवं प्राकृतिक समिति ने प्रगतिशील होकर विभिन्न संविधानों का विश्लेषण कर भारतीयों की आकांक्षाओं के अनुरूप जीवंत, प्रगतिशील, सतत विकास का मार्गदर्शी संविधान को बनाया है, जो अपनी प्रकृति में अद्वितीय है।

17. क्या भारत सरकार में अधिसंख्य मंत्रालयों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है? प्रासंगिक तर्कों के साथ विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Is there a need to rationalize the large number of ministries in the Government of India? Discuss with logical arguments. (Answer in 200 words) 12.5

भारत सरकार अपने कार्यों का सुचारु संचालन हेतु विभिन्न मंत्रालयों का गठन कर जनकल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देता है। जैसे - हालिया समय में 'जल शक्ति मंत्रालय' तथा 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया गया। वर्तमान परिदृश्य में उपजे नवीन विषयों जैसे डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण 2.0, महामारी, पर्यावरणीय मुद्दे आदि को देखते हुए भारत सरकार के मंत्रालयों को अधिक युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।



(1) कोऑर्डिनेशन (सामंजस्य) का अभाव

- विभिन्न मंत्रालयों के मध्य आपसी सामंजस्य नहीं
- किसी पक्ष के समस्त आयामों का अध्ययन अप्रभावी
- मंत्रालयों के मध्य वैचारिक भिन्नता।

जैसे - उद्योग एवं परिवहन मंत्रालय किसी जंगल को काटने का निर्देश देता है परन्तु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय / जनजातीय मंत्रालय इसे रोक देता है।

(2) नवीन मुद्दों से अनभिज्ञ → बढ़ती आतंकवादी घटनाएँ, वैश्विक अराजकता, पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी मुद्दे, जल तनाव, अंतरिक्ष एवं समुद्र प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन, NFT जैसी चौथी औद्योगिक क्रांति एवं Web 3.0 जैसी वैश्विक मुद्दों की जगह परम्परागत मुद्दों पर ही ध्यान।

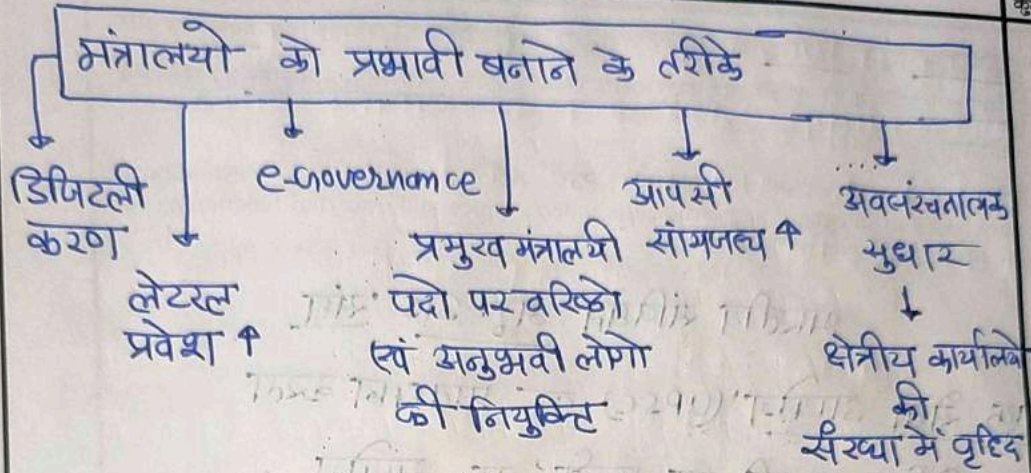
(3) डिजिटलाइजेशन की कमी → विभिन्न मंत्रालयों में फाइलों पर कार्य होना, वेबसाइट

का सही से कार्य नहीं करना, जनता द्वारा मंत्रालयों पर ई-मेल, FAX से कन्टेक्ट करने पर प्रति उत्तर का अभाव इत्यादि समस्याएँ हैं।

(4) प्रशासनिक तंत्रों का अत्यधिक प्रभाव

↓  
जनभागीदारी से पूरी।

Don't write anything this margin (इस मार्ज में कुछ ना लिखें)



हालिया समय में भारत सरकार ने गति-शक्ति मिशन, वैश्विक एवं गंभीर बुद्धि पर नवीन मंत्रालय जैसे जल शक्ति मंत्रालय तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर जन हिंसी शासन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है

18. यू.पी.एस.सी. की भूमिका का विवरण दीजिए। साथ ही, यू.पी.एस.सी. की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज की सुरक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सूचीबद्ध कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Provide an account of the role of UPSC. Also, enumerate the Constitutional provisions to safeguard and ensure the independence and impartial functioning of the UPSC. (Answer in 200 words) → 12.5

भारतीय संविधान अनु. 315 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) का प्रावधान करता है। 'मेरिट पद्धति का प्रहरी' यह आयोग एक 'संवैधानिक संस्था' है जो विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करती है।

यू.पी.एस.सी. (UPSC) की भूमिका

- विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से प्रमुख अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति।  
जैसे- UPSC- सिविल सेवा परीक्षा, UPSC-CAPF  
UPSC- IAS इत्यादि।
- भर्ती संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना जो इन रिपोर्टों को संसद में पेश करते हैं।
- सामाजिक न्याय → DoPT भारत सरकार की सहायता से।
- विभिन्न अधिकारियों के संबंध में कोई जानकारी प्रदान करना आदि।

यूपीएससी देश की सर्वोच्च सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करती है अतः इसके निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना आवश्यक है। अतः इसके कामकाज की सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नवत हैं -

- (1) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल के समय उनके वेतन में नकारात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा। (अनु-315)
- (2) UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन अनुसूची-2 के तहत संघ की संचित निधि (266) पर आधारित होगा।
- (3) अध्यक्ष द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। सदस्यों में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
- (4) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, PM की सलाह पर करेंगे परन्तु बख्तिखान की सुप्रीम कोर्ट में जांच के पश्चात ही की जा सकती है।

(5) यूपीएसी (UPSC) प्रत्यक्षतः क्विटी मंत्रालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह आयोग कर्मिक मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करता है तथा राष्ट्रपति एवं भारतीय संविधान के प्रति जवाबदेह है।

इसी प्रकार के प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग को भी प्रदान किए गए हैं। स्पष्टतः इन तरीकों से यह आयोग निष्पक्ष एवं प्रभावी तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करता रहेगा।

19. अधिकरण क्या हैं? अनुच्छेद 323A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B से किस प्रकार भिन्न है? (उत्तर 200 शब्दों में दें)

What are tribunals? How is Article 323A different from Article 323B of the Indian Constitution? (Answer in 200 words)

12.5

अधिकरण एक अर्थ -

व्यापक निकाय होता है जिसका वर्णन

भारतीय संविधान भाग 14 क तथा

अनुच्छेद 323 (क) एवं 323 (ख) में किया

गया है जैसे - NDT, CAT इत्यादि।

भाग 14 'क'

अनु. 323 (A)

↓  
प्रशासनिक  
अधिकरण।

अनु. 323 (B)

↓  
प्रशासनिक अधिकरण  
के अलावा अन्य  
भारत से संबंधित  
अधिकरण।

अनु. 323 (A) तथा 323 (B) में अंतर

अनु. 323 (A) → प्रशासनिक अधिकरणों का

सावधान (CAT)

↓  
सार्वजनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों  
को अपनी <sup>प्रशासनिक</sup> समस्याओं के विरुद्ध शिकायत

करने का एक सैद्धान्तिक उपकरण है।  
→ इसके विरुद्ध HC → SC में अपील की  
की जा सकती है।

जैसे- हालिया समय में पश्चिम बंगाल के  
अचिव ने अपनी शिकायत को CAT  
में दर्ज किया था।

**अनुच्छेद 323 B**

→ अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों  
का वर्णन किया गया है।

इसमें शामिल है → पर्यावरण संबंधी विषय

→ नीति उद्यम संबंधी

अधिकरण इत्यादि।

स्पष्टतः अधिकरण महत्वपूर्ण

अहर्द व्यापिक निकाय होते हैं जो न्यायपालिका

के कार्यों का बोझ कम कर 'न्याय तक

सबकी पहुँच' के सिद्धांत को बहावा देते हैं।

20. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर अधिरोपित किया जा सकता है? साथ ही, इसके अधिरोपण की प्रक्रिया तथा इसके प्रभावों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

On what grounds can President's Rule be imposed in a state? Also, mention the procedure of its imposition and its effects. (Answer in 200 words) 12.5

### भारतीय संविधान अनु. 356

राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है यह किसी राज्य में अनु. 355 का उल्लंघन होने पर राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है।

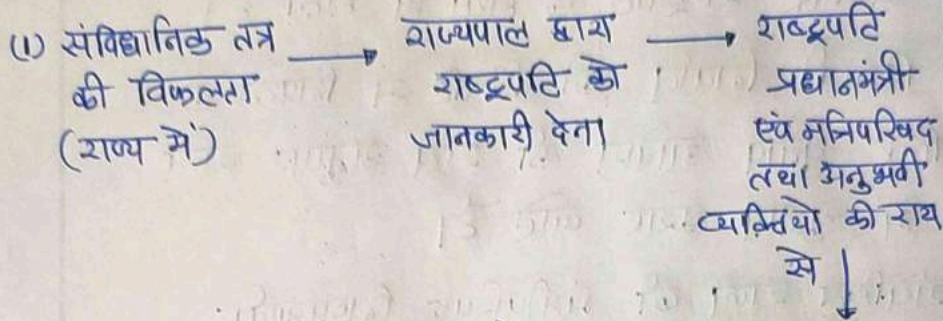
#### राष्ट्रपति शासन के आधार

- (1) राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं चल रही हो।
- (2) अनुच्छेद 355 की स्थिति में जब राज्य, केन्द्र सरकार की किसी विधि को नहीं मान रहा हो।
- (3) स्पष्ट बहुमत का आभाव अथवा राज्यपाल यह अधिसूचित कर दे कि किसी भी दल के पास पर्याप्त जनाधार नहीं है तथा दोबारा चुनाव नहीं कराया जा सकता।



अथवा विधायी निवृत्ति की स्थिति में

## राष्ट्रपति शासन अधिशेषण की प्रक्रिया



राज्य की लगभग विधायी कार्यपालक, प्रशासनिक शक्तियाँ → राष्ट्रपति में → राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।

## राष्ट्रपति शासन के प्रमुख प्रभाव

(क) शक्तियों का संकेन्द्रण → राष्ट्रपति में

विधायी शक्ति

कार्यपालक शक्ति

प्रशासकीय शक्ति

वित्तीय शक्ति

President

(ख) विभिन्न बिलों को रोक देता है।

→ राज्य के लिए धन विधेयक इत्यादि रोक देता है।

→ केन्द्रीय बजट में राज्य के बजट सबधी प्रावधान किए जाते हैं।

- (ग) अधिकतम 3 साल तक राज्य की समस्त बाग़ेबे राष्ट्रपति के हथे में होती है।
- (घ) विद्यार्थी निवर्तन की स्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग की राय अनुसार राज्य में चुनाव कराए जाते हैं।
- (ङ) संबंधित राज्य की मंत्रीपरिषद् निष्प्रभावी हो जाती है।
- (च) राज्य के लिए अध्यादेश का निर्माण किया जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन सख्खरी संघवाद की छवि को धूमिल करता है अतः इसका प्रयोग अपवाद स्वरूप स्थिति में राजनीतिक मंशा से निश्चेक्ष होकर राष्ट्रहित में ही करना चाहिए।